

मुख्य संघिव की अध्यक्षता में सोलर पम्प स्थापना की योजना के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्य शासन ने सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सर्व योजना के क्रियावृत्तन के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन मुख्य सचिव की अधिकृत में किया है। समिति में सचिव उज्ज्वल, वित्त, नगरीय एवं ग्रामीण विकास, गोपनीय एवं प्रौद्योगिकी, सदस्य एवं नवीन तथा नवकर्णीय उज्ज्वल विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे। राज्यस्तरीय समन्वय समिति द्वारा योजना के सभी घटकों अंतर्गत प्राप्ति की नियमित समीक्षा की जायेगी। योजना के क्रियावृत्तन के लिए विभागों के बीच आवश्यक समन्वय योजना की प्राप्ति की नियमित (अधिकारी 3 माह) में समीक्षा की जायेगी, ताकि समय-सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। योजना को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक विनिर्देश जारी करना, योजना क्रियावृत्तन के संबंध में भास्त राज्य सरकार के नवीन एवं नवकर्णीय उज्ज्वल भास्त एवं साथ समन्वय करना और राज्य में योजना क्रियावृत्तन में सुधार के उपयोग के सुधार भी समिति द्वारा दिए जायेंगे।

शासकीय सेवकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाकर

55 प्रतिशत किया गया, आदेश जारी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को बढ़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में बढ़ि का आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के तहत अनेक वाले कर्मसुखियों के वेतनमान 15 लक्ष मंहगाई भत्ते के स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3 बड़क 53 प्रतिशत किया गया है, विभाग के भुगतान अग्रसर 2024 के वेतन में होगा इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2 बड़क की बढ़ि कर इसे कुल 55 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फेब्रुअरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस बढ़ि का सुवासिक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जन से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मसुखियों के परियोजनों के एरियर को पूरी राशि का अगल पूर्णांक रूप से पूर्णांकित किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस भुगतान का संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान के संबंधित विभाग के उपरांत नहीं होना चाहिए।

प्रदेश में 15 हजार इंको लब गठित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये विद्यालयों में बच्चे के कलब का गठन लगातार किया जा रहा है। अब तक 15 हजार इंको के कलब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 से यूथ एड इंको के कलब के गठन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये थे। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इंको के कलब की गतिविधियों के संबंध में केलेंडर जारी किया जाता है। शैक्षणिक लाभ 2024-25 में 5 से 12 जून, 2024 तक राज्य में पर्यावरण समाज के अंतर्गत समर कैप्य का आयोजन किया गया। कैप्य में एक ऐड मॉड के नाम "अभियान, जल शक्ति अभियान, सम्पर्काणीय जीवन-शैली संबंधित गतिविधियाँ" इंको हेकाथन के साथ निर्धारित अत्याधुनिक जल शैली की गयी। निंबंध प्रतियोगिता का शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये पायावरण पर केंद्रित केलेंडर तैयार किया जा रहा है। केलेंडर के अनुसार इंको के कलब में विद्यालयों की गतिविधियों सुनिश्चित की जायेगी।

विचार

चीन ने पाकिस्तान को सौंपी पीएल-15 मिसाइल प्रणाली

चीन ने पाकिस्तान को अपनी उन्नत पीएल - 15 एयर-टू-एयर मिसाइल प्रणाली सौंप दी है जिससे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चीन अब खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। जिसके कारण भारत की परेशानी आगे चलकर बढ़ सकती है यह मिसाइल लॉन्च-रेंज एयर टू-एयर कैटेगरी की है। जिसकी मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर की बताई जा रही है। पीएल - 15 मिसाइल को चीन ने आधुनिक लड़ाकू विमानों जे - 10सी और जे - 20 के साथ जोड़ा है। चीन इस सिस्टम को पाकिस्तान वायुसेना के जेएफ - 17 ब्लॉक-3 फाइटर जेट्स में शामिल करने में चीन द्वारा मदद की जा रही है। चीन की यह कार्यवाही चीन-पाकिस्तान के बीच ठोस रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को जो रक्षा प्रणाली दी थी वह भारत की रक्षा प्रणाली का मुकाबला नहीं कर पाई। जिसके कारण पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने लक्ष्य पर निशाना साधकर सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने और पाकिस्तान की सुरक्षा प्रणाली को जिस तरह से भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। उससे पाकिस्तान के साथ-साथ चीन की चिंता भी बढ़ गई है। चीन ने अपनी सबसे उन्नत पीएल-15 एयर टू-एयर प्रणाली पाकिस्तान में तैनात कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, इससे भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस युद्ध का लाभ चीन भी लेना चाहता है। वर्तमान स्थिति में चीन के दोनों हाथ में लड़ रहा है। एक हाथ में पाकिस्तान है, दूसरे हाथ में भारत है। पीएल - 15 मिसाइल भारतीय वायुसेना के राफेल और तेजस जैसे विमान को लंबी दूरी से निशाना बना सकती है। यह मिसाइल सक्रिय रडार होमिंग प्रणाली से लैस है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने में इसे सक्षम माना जाता है। भारत और पाक के बीच में जब युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में चीन द्वारा पाकिस्तान को जो सैन्य सहायता दी जा रही है। वह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत का दोनों देशों के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है। वर्तमान स्थिति का चीन फायदा उठाना चाहता है। वह पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। निश्चित रूप से चीन की प्रतिस्पर्धा भारत के साथ है। भारत जितना कमज़ोर होगा, उतना ही वह चीन के ऊपर निर्भर होगा, ऐसा हमेशा से चीन सोचता है। पिछले एक दशक में चीन ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह के रिश्ते विकसित किए हैं। भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता देते हुए। उन देशों के साथ व्यापारिक और सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। भारत की पड़ोसी देशों के साथ दूरियां बढ़ी हैं।

जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उत्तराधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने डॉटरों को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने एवं किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने की नसीहत देकर न केवल गरीब मरीजों को राहत पहुंचाई है बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त मनमानी, मूल्यहीनता, रिश्वत एवं अनैतिकता पर अंकुश लगाने की दिशा में सराहनीय एवं प्रासंगिक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जर्जों की पीठ संदीप मेहता, विक्रम नाथ और संजय करोल ने दवा कंपनियों से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। इस याचिका में दवा कंपनियों पर मनमानी एवं रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पूरे देश में इस फैसले का पालन हो, तो इससे अहम सुधार हो सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-डॉटरों पर असर दवा कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप लगता है।



ऐसे में अगर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखेंगे, तो उनपर लगने वाले इलाजम का मुझा भी हल हो जाएगा। ऐसा करने से एक बड़ी आबादी को सस्ती एवं अचुक दवाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जेनेरिक दवाइयों को जनवायी बनाने की दिशा में सार्थक पहल की है। पूरी दुनिया में जेनेरिक दवाइयों को ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन दवा माफिया इसमें बाधाएं खड़ी कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता से दवा कंपनियों व चिकित्सकों के अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जा सकता है, जो बड़ी आबादी की एक बड़ी समस्या का सटीक समाधान होगा। निविदा ही डॉक्टर अगर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखते तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी बढ़ दी सकती है। शार्प अदालत उस याचिका पर मुनवार कर रही थी जिसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की समान सर्विस पर कानून बनने तक दवा कंपनियों को अनैतिक विषयन प्रथाओं को नियंत्रित करने के दिशा-निर्देश की मांग की गई थी। भारत में किफायती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन एवं प्रचलन एक जीवन रेखा है, लेकिन इसके गुणवत्ता के आश्वासन को मजबूत करने के साथ

डॉक्टरों की मनमानी पर नियंत्रण करना होगा, जिसमें सौन्दर्य न्यायालय की पहल एक रोशनी बनेगा। आज जबकि देश में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे-जैसे चिकित्सा-विज्ञान का विकास हो रहा है, नवी-नवी बीमारियां एवं उनका महंगा इलाज एवं महंगी दवाइयां बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसलिये जेनेरिक दवाओं पर भरोसा और दुनिया में इसकी मांग, दोनों में इजाफा हुआ है। मोर्दी सपाका ने जेनेरिक दवाओं को ज्यादा स्वीकार्य बनाने एवं सर्वसूलभ करकर एक अधिनव स्वास्थ्य क्रांति का स्रोतपत किया है।

जेनेरिक दवाएं, जो ब्रॉडेंड दवाओं को कस्ता विकल्प होती हैं, वही सक्रियता तत्व (प्रिक्टर इंडिएंट) रखती हैं और उतनी ही अधिक बावजूद भरोसा का उत्पादन एवं समर्थन करते हैं। फिर भी, इनका उत्पादन अप्रैक्षिक अदालत उस याचिका पर मुनवार कर रही थी जिसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की समान सर्विस पर डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं, एक स्वैच्छिक सहित है, जिसका पालन डॉक्टर अपनी मर्जी से करते हैं। कोर्ट ने दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर अत्याधिक बोल लगाने के लिए दिशा-

निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट की यह टिप्पणी स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। यहां नहीं, आप जनता को सस्ती और सुलभ दवाओं का भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारत में दवा उद्योग एक विशाल और जटिल क्षेत्र है, जहां दवा कंपनियां अक्सर अपने मुनाफे को बढ़ावा देकर यहां पर उपयोग, विदेश यात्रा, महंगे रिपोर्टोर और अन्य प्रोलोग्य देकर अपनी ब्रॉडेंड दवाओं को प्रचारित करती हैं। नवीजन, डॉक्टर कई बार मरीजों को ऐसी दवाएं लिखते हैं, जो न केवल महंगी होती हैं, बल्कि कई बार अनावश्यक भी होती हैं। इसका सीधा असर मरीजों की जेब और स्वास्थ्य पर पड़ता है।

सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रचलन को आधिक करने की रणनीति एक वैश्विक समस्या है। इस तरह में जेनेरिक दवाओं की शुरूआत मोर्दी सरकार ने की। वैसे 2004 और 2013 के बीच अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को इससे लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की बचत हुई है। जेनेरिक केसर जैसी अनेक असाध्य बीमारियों की दवाओं की समय पर उपलब्धता ने ऐसे कई रोगियों की सामर्थ्य देखा जाता है। जबकि इसके विपरीत अनेक परिजनों के गंभीर व असाध्य रोगों की महंगी होती है, जबकि इसके दवाओं में इलाज से लाभों लोग गोरी की दलदल में ढूँढ़ गए। कोरोना संकट के दौरान भी लोग द्वारा घर, जैवर व जेवर बेचकर अपनों की जान बचाने की कोशिश की खबरों में तैरती रही। लेकिन सामाजिक दिनों में दवा कंपनियों की मिलीभगत व दबाव में लिखी जाने वाली महंगी दवाइयां भी गोरीओं के लिये बड़ी समस्या बनती रही हैं। इसके बावजूद किंवदं विदेशी दवाएँ जैसे चलते हैं। बृहत् समय पहले केंद्र सरकार की जेनेरिक दवाइयां लिखने की अनिवार्यता का दिनेश का अच्छाया हुआ, जिसके चलते निर्णय वापस लगा पड़ा था। अब इसी चिंता को देख की शीर्ष अदालत ने अधिकृत किया है, जो गोरीबों के सस्ती दवाओं से एक स्वास्थ्य उत्तराधिकारी असर देगा।

विदेशी दवाएँ एवं दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि दवा कम्पनियों तरह-तरह के प्रलोग्य व परोक्ष-अपरोक्ष लाभ देकर चिकित्सकों पर महंगी दवा लिखने के दबाव बनती हैं, मानो सारे नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर धनार्जन ही एकमात्र कर्म रह गया है। जिसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है, जो महंगी दवा खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में वे कर्ज लेकर या अपने रिश्वतदारों से मदद लेकर किसी तरह गोरीबों का इलाज करते हैं। इसके खिलाफे एक प्रभावी गोरीब है। गोरीब-गोरीब मरीज इलाज से चैर्चिंट रखते हैं और उनके दबाव के बीच विकास नहीं होता है। गोरीब-गोरीब सरकारों को इलाजम नहीं लगता है। वृद्ध समय देखने के दबाव के बीच विकास नहीं होता है। एक संकट दवाइयों द्वारा इसपर लगता है। लेकिन विदेशी दवाएँ जैसे इलाज देती हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक संकट दवाइयों द्वारा इसपर लगता है कि दवा कंपनियों को उत्पादन करने के लिये एक गोरीब घटक होता है। यदि दवा नियंत्रित रहती है तो उत्पादन करने के लिये एक गोरीब घटक होता है। यदि दवा कंपनियों को उत्पादन करने के लिये एक गोरीब घटक होता है। यदि दवा कंपनियों को उत्पादन करने के लिये एक गोरीब घटक होता है। य

